



यहां हर खरीदारी में छिपा है एक जेम

डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक खरीद का रूपांतरण

08 अगस्त 2026

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने मानवीय और बिखरी हुई प्रक्रियाओं को एक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-आधारित डिजिटल मंच से बदलकर सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में क्रांति ला दी है। संपूर्ण खरीद चक्र का डिजिटलीकरण करके, जेम ने दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार किया है, साथ ही लेन-देन की लागत को भी कम किया है। एमएसई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और सामाजिक तौर पर वंचित उद्यमों के लिए समर्पित पहलों ने सरकारी बाजारों तक पहुंच का विस्तार किया है, जिससे खरीद प्रक्रिया अधिक समावेशी बन गई है। भारत के डिजिटल खरीद इकोसिस्टम के एक प्रमुख स्तंभ के तौर पर जेम, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस जैसे लक्ष्यों में सहयोग कर रहा है।

डिजिटल दौर में सार्वजनिक खरीद

हर साल, सरकारें कई क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपये के सामान और सेवाओं की खरीद करती हैं। चिकित्सा उपकरण और कक्षाओं के लिए फर्नीचर से लेकर परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल समाधानों तक, खरीद प्रक्रिया सार्वजनिक प्रशासन के लगभग हर पहलू को सहयोग प्रदान करती है।

पारंपरिक खरीद प्रक्रिया में आमतौर पर कागजी कार्रवाई, कई स्वीकृतियां और लंबी निविदा प्रक्रियाएं शामिल होती थीं, जिससे दक्षता और पारदर्शिता सीमित हो जाती थी। इस प्रणाली के रूपांतरण के लिए, सरकार ने 9 अगस्त 2016 को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) की शुरुआत की।

पारंपरिक खरीद से डिजिटल बाजार की ओर

सार्वजनिक खरीद में एक क्रांतिकारी बदलाव के तौर पर परिकल्पित जेम, एक एकीकृत, एंड-टू-एंड डिजिटल मंच है। यह सरकारी खरीदारों को एक सुरक्षित, कागजी, नकद रहित और संपर्क रहित प्रणाली के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने में योग्य बनाता है। यह खरीदारों और विक्रेताओं को एक साझा ऑनलाइन बाजार में लाता है, जिससे खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, कुशल और प्रतिस्पर्धी बनती है।

इस मंच को वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की अग्रणी सार्वजनिक खरीद प्रणालियां शामिल हैं। यह खरीद प्रक्रिया को सरल और मानकीकृत करने के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करता है। सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन के जरिए इसके कार्यान्वयन को और सुदृढ़ किया गया, जिससे सरकारी संगठनों को प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद करने की सुविधा मिली।

जेम केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, पंचायतों और सहकारी समितियों सहित सरकारी खरीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला को सेवाएं प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म विक्रेता पंजीकरण और उत्पाद सूचीकरण से लेकर बोली प्रक्रिया, अनुबंध आवंटन, ऑर्डर पूर्ति और भुगतान तक संपूर्ण खरीद प्रक्रिया को डिजिटल रूप देता है। इससे अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित होता है।

जेम की पहलों, नवाचारों और प्रभाव के बारे में [अधिक जानें](#)।

एक पारदर्शी खरीद प्रणाली का निर्माण

जेम के खरीद संबंधी फ्रेमवर्क में पारदर्शिता सर्वोपरि है। यह मंच सरकारी खरीद में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, मानकीकृत प्रक्रियाओं और डेटा-आधारित निर्णय लेने को सक्षम बनाता है। सरकारी खरीदार अपनी जरूरतों के अनुसार प्रत्यक्ष खरीद, तुलना, इलेक्ट्रॉनिक बोली और रिवर्स नीलामी के माध्यम से खरीद कर सकते हैं। डिजिटल रिकॉर्ड, त्वरित समय पर निगरानी और स्वचालित कार्यप्रवाह जवाबदेही बेहतर करते हैं और विवेकाधीन निर्णयों को कम करते हैं।

सही निर्णय लेने में मदद के लिए, जेम डेटा-आधारित उपकरणों और एकीकृत सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है।

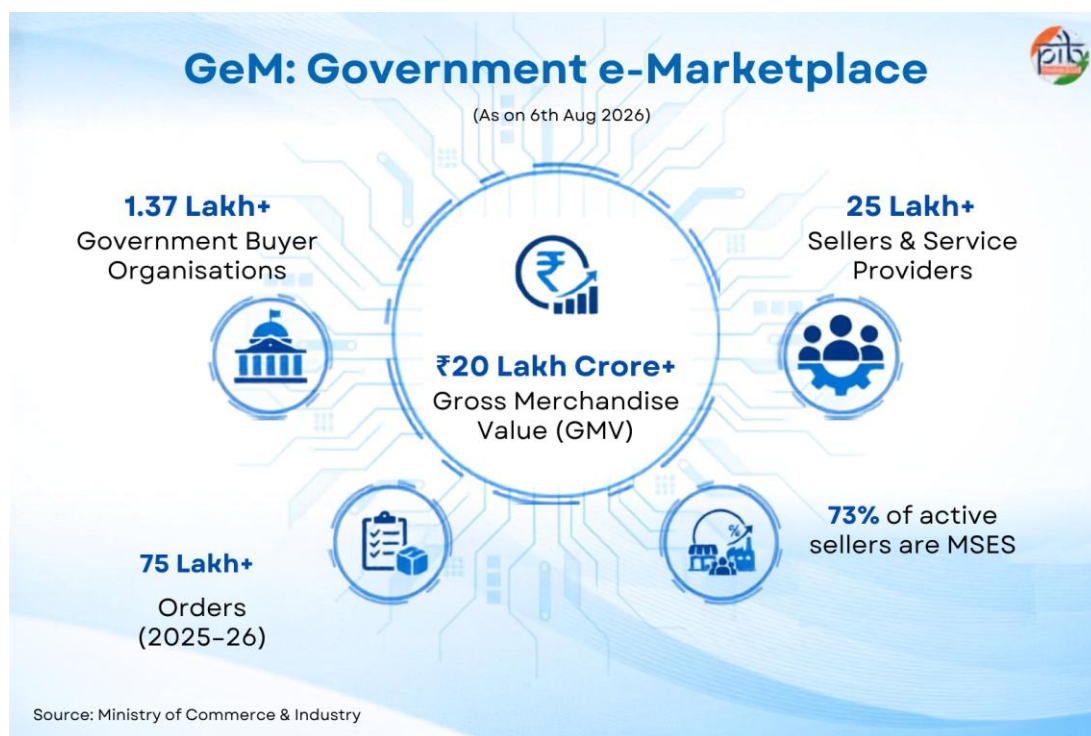
- खरीदार जेम उपलब्धता रिपोर्ट और पिछले लेन-देन का सारांश देखकर जेम के बाहर खरीदारी करने से पहले उत्पाद की उपलब्धता और पिछले खरीद रुझानों का आकलन कर सकते हैं।
- व्यावसायिक विश्लेषण सुविधाएं अंतिम खरीद मूल्य, मूल्य का रुझान और विभागीय खरीद इतिहास जैसी जानकारी प्रदान करती हैं। इससे खरीदारों को सोच-समझकर और लागत संबंधी खरीद निर्णय लेने में मदद मिलती है।
- केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) के साथ एकीकरण से देश भर में की गई कई खरीद संबंधी सरकारी निविदाओं की जानकारी के लिए एक ही जगह पर पहुंच प्राप्त होती है।
- भारतीय रेलवे इलेक्ट्रॉनिक खरीद प्रणाली (आईआरईपीएस) और रक्षा सार्वजनिक खरीद पोर्टल (डीपीपीपी) की कार्यक्षमताओं को जेम के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिससे एक एकीकृत और अंतरसंचालनीय सार्वजनिक खरीद प्रणाली का निर्माण किया जा सके।

क्या आप जानते हैं?

सैन्य मामलों के विभाग का कुल जीएमवी 6 अगस्त 2026 तक **21.35 लाख करोड़** से अधिक हो गया।
6 अगस्त 2026 तक जेम के कुल जीएमवी में रक्षा खरीद का योगदान **14.93%** से अधिक रहा।

सार्वजनिक खरीद के दायरे का विस्तार

जेम 1.37 लाख से अधिक सरकारी खरीदार संगठनों को लगभग 25 लाख विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से जोड़ता है, जिससे ₹20 लाख करोड़ से अधिक की कुल खरीद को आसान बनाया जा सकता है।



लेन-देन को आसान बनाने के साथ ही, जेम भारत के डिजिटल खरीद तंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कार्यक्रमों में सहयोग करता है। यह 10,660 से अधिक उत्पाद श्रेणियों और 350 सेवा श्रेणियों के साथ एक व्यापक डिजिटल बाजार प्रदान करता है, जो सरकार की कई खरीद संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। इस बाजार में चिकित्सा उपकरण, फर्नीचर, कंप्यूटर, अग्रिशमन उपकरण और हस्तशिल्प के साथ-साथ परिवहन, खानपान, वाहन किराए पर लेना और मानव संसाधन सेवाएं जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। कई खरीद माध्यम, एकीकृत भुगतान प्रणाली और ऑनलाइन अनुबंध निर्माण पारदर्शी, कुशल और संपूर्ण डिजिटल खरीद सुनिश्चित करते हैं।

नीतिगत सुधारों, तकनीकी अपग्रेड और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से जेम का निरंतर विकास जारी रहा है। हाल के सुधारों में आवर्ती खरीद के लिए दर अनुबंध और विक्रेताओं के लिए जमानत राशि की जरूरत को खत्म करना शामिल है। इन सुधारों ने खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया है।

जेम इकोसिस्टम को मजबूत करने वाली साझेदारियां

जेम ने सार्वजनिक खरीद को अधिक नवीन, पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए सरकारी संस्थानों, वित्तीय संगठनों, उद्योग निकायों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ रणनीतिक साझेदारियां स्थापित की हैं।

- **नवाचार:** अप्रैल 2025 में, जेम ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) और ड्रोन खरीद के लिए ड्रोन फेडरेशन इंडिया (डीएफआई) के साथ साझेदारी की।
- **वित्त:** जेम सहाय पहल के तहत, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी से पंजीकृत विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार हुआ है।

जेम सहाय

जेम सहाय एक विशेष मोबाइल ऐप है जो जेम पर मौजूद योग्य स्वामित्व वाले विक्रेताओं को तत्काल, बिना किसी गिरवी के कार्यशील पूंजी लोन प्राप्त करने के लिए उपलब्ध बनाता है। यह खरीदार की सहमति के बिना त्वरित, कागजी वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे विक्रेताओं को सरकारी आदेशों को सुचारू रूप से पूरा करने में मदद मिलती है।

- **क्षमता निर्माण:** अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजएनआईएफएम), केयरएज रेटिंग्स, राष्ट्रीय माल प्रशासन केंद्र (एनसीजीजी) और भारतीय लोक प्रशासन

संस्थान (आईआईपीए) के साथ किए गए समझौता ज्ञापनों में सार्वजनिक खरीद में अनुसंधान, प्रशिक्षण, जानकारी के आदान-प्रदान और नीति विकास में सहयोग करते हैं।

- **अनुपालन:** मानव संसाधन आउटसोर्सिंग सेवाओं में पारदर्शिता बेहतर करने और अधिनियमों के अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)** के साथ एकीकरण।
- **समावेशन:** यूएन वुमन के साथ साझेदारी, वुमानिया पहल के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को प्रोत्साहन देती है, जिससे लैंगिक रूप से संवेदनशील और समावेशी सार्वजनिक खरीद को प्रोत्साहन मिलता है।

महिलाओं, स्टार्टअप और सामाजिक तौर पर हाशिए पर पड़े उद्यमियों का सशक्तिकरण

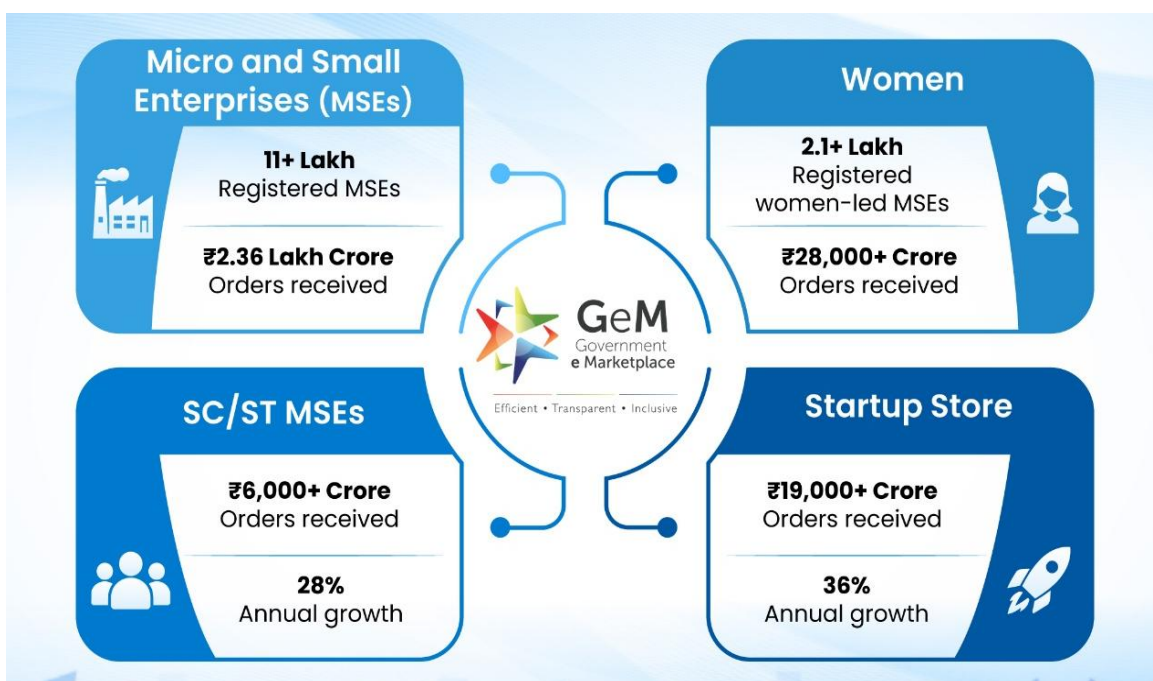
सरकारी खरीद तक अति म छोर की पहुंच को सद्ृढ़ करनेके लिए, जेम ने जून 2026 में कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी-एसपीवी) के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के अंतर्गत, चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रायोगिक आधार पर 50 जेम सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

जेम सुविधा केंद्र जागरूकता, विक्रेता पंजीकरण, विक्रेता मूल्यांकन, कैटलॉग निर्माण, क्षमता निर्माण और शिकायत निवारण के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर सहायता प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य सरकारी खरीद में एमएसई, महिला एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमियों, स्टार्टअप्स, कारीगरों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय निर्माताओं की भागीदारी बढ़ाना है।

जेम के माध्यम से समावेशी विकास (2025-26 में)

इस प्लेटफॉर्म ने सरकारी खरीद में पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित भागीदारी को योग्य बनाकर पारंपरिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए बाजार पहुंच में विस्तार किया है।

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई): 11 लाख से अधिक पंजीकृत एमएसई ने ₹2.36 लाख करोड़ से अधिक मल्यू के 51 लाख से अधिक ऑर्डर पर किए।
- महिला नेतृत्व वाले उद्यम: 2.1 लाख से अधिक पंजीकृत महिला नेतृत्व वाले एमएसई ने ₹28,000 करोड़ से अधिक मल्यू की खरीद हासिल की।
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यम: खरीद ₹6,000 करोड़ से अधिक रही, जिसमें लगभग 28% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- स्टार्टअप: खरीद ₹19,000 करोड़ से अधिक रही, जिसमें 36% से अधिक की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई।



समावेशी भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए, जेम ने स्वायत्त, स्टार्टअप रनवे 2.0, वुमनिया और सरस कलेक्शन जैसी विशेष पहलें शुरू की हैं। ये पहलें स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), कारीगरों और अन्य वंचित समुदायों के लिए बाजार तक पहुंच में सुधार करती हैं।

स्वायत्त पहल: स्वायत्त (स्टार्टअप, महिलाओं और युवाओं को ई-लेनदेन के माध्यम से लाभ पहुंचाना) समावेशी सार्वजनिक खरीद को प्रोत्साहन देने वाली जेम की प्रमुख पहल है। यह स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों, एमएसई और स्वयं सहायता समूहों को सरकारी खरीदारों को अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बनाती है।

वुमनिया: यह पहल जेम पर महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) की ओर से निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करती है। यह उन्हें सरकारी खरीद के अवसरों तक पहुंचने और अपने बाजार का विस्तार करने में मदद करती है। **वुमनिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां पढ़ें।**

सरस कलेक्शन: एक विशेष बाजार श्रेणी के अंतर्गत, सरस कलेक्शन ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की ओर से निर्मित दैनिक उपयोग के उत्पादों को प्रदर्शित करता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एसएचजी को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों तक बाजार की पहुंच प्रदान करना है।

स्टार्टअप रनवे 2.0: यह स्टार्टअप्स को सरकारी खरीदारों के समक्ष अपने नवोन्मेषी उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने और सार्वजनिक खरीद में शामिल होने के लिए एक समर्पित बाजार प्रदान करता है।

स्मार्ट सार्वजनिक खरीद की ओर

जेम अपने 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और अब इसका ध्यान एक अधिक स्मार्ट और एकीकृत सार्वजनिक खरीद प्रणाली की ओर केंद्रित हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और व्यापक भागीदारी पारदर्शिता, दक्षता और शासन को और मजबूत करेगी। सरकारी मांग को स्थानीय उद्यमों से जोड़कर, जेम 'वोकल फॉर लोकल', 'मेक इन इंडिया' और समावेशी आर्थिक विकास

को प्रोत्साहन दे रहा है। जेम भारत को डिजिटल रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में लगातार मदद कर रहा है।

संदर्भ

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201284®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2274872®=3&lang=1>

https://doe.gov.in/files/circulars_document/FInal_GFR_upto_31_07_2024.pdf

https://assets-bg.gem.gov.in/resources/upload/shared_doc/gem-chronicle-december-2025-edition_1766729032.pdf

<https://eprocure.gov.in/cppp/newsletterdisp/kbadqkdlcswfjdelrquehwuxcfmijmuixngudufgbuubgubfugbububjxcgfvvsbdihbqfGhdFgFHtyhRtNjl2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1897442®=48&lang=2>

<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/mar/doc202131041.pdf>

पीआईबी अभिलेखागार

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=156611&ModuleId=3®=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/factsheetdetails.aspx?id=148586®=48&lang=2>

पीआईबी शोध

पीके/केसी/एमएम